LOSSES IN FOODGRAINS DUE TO PESTS

1197. SHRI CHENGLARAYA NAIDU: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have asked all the State Governments to take immediate measures to reduce the rate of foodgrain losses due to pests particularly insects and rodents;

(b) If so, whether the States have also been asked to draw up a coordinated plan for the protection of the foodgrains;

(c) if so, the reaction of the State Governments thereto; and

(d) whether Government are giving any assistance to the State Governments in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The State Governments have been asked to send the first quarterly report in December, 1967. They were also requested to report the action taken on the letter. No reply has been received so far.

(d) The State Governments have been asked to avail of such technical assistance as they may desire from the Central Government.

मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

1198. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये 30,000 टन अतिरिक्त खाद्यान्न सप्लाई करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां । एक टन भेजा गया था ।

(ख) पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि गत दो वर्षों में मानसून के असफल रहने के कारण राज्य में फसलों की स्थिति बिगड़ गयी थी । 1966-67 में 55·83 लाख मीटरी टन खाद्यान्न पैदा हुये थे जबकि वार्षिक आवश्यकता 82 लाख मीटरी टन (मानव उपयोग के लिये 74·64 लाख मीटरी टन और शेष बीज के लिये) थी और इस प्रकार 26·17 लाख मीटरी टन की कमी थी । यह भी कहा गया था कि आगामी दो महीनों में स्थिति और बिगड़ने की सम्भावना थी और इसलिये 30,000 मीटरी टन प्रति मास का अतिरिक्त आवंटन भेजा जाना चाहिये ताकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की जनता भुखमरी महामारी का शिकार न हो ।

(ग) केन्द्रीय आरक्षित भण्डार में उपलब्धि और भयंकर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई में यथासम्भव सीमा तक वृद्धि की गयी थी ।

LABOUR FOREST COOPERATIVE SOCIETIES IN ORISSA AND ANDHRA PRADESH

1199. SHRI V. NARASIMHA RAO : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of Labour Forest Cooperative Societies in Orissa and Andhra Pradesh in each District and the amount of loan granted to them during the last three years;

(b) The amount sanctioned to the Siali Labour Forest Cooperative Society in